



हर रिश्ते का रखे ख्याल...

तो सवाल ये है, ओसवाल सोप ही क्यों?

ये बना है
नेचुरल ऑयल्स सेखारे पानी में भी
कपड़े करे साफ़कम गले
ज्यादा चलेकपड़ों और हाथों का
रखे ख्याल

इसलिए हर घर का भरोसेमंद नाम
ओसवाल सोप



Product image is for illustrative purposes only and may differ from the actual product

ओसवाल सोप ग्रुप - हर रिश्ते का रखे ख्याल

सोप एवं टब सोप



अधिक जानकारी के लिए
+91 91161 71956, 96802 01956 पर कॉल करें

विपणन :
उत्तम चन्द देसराज





हर रिश्ते का रखे ख्याल...

ओसवाल सोप ग्रुप



6 करोड़ परिवारों का विश्वास

क्वालिटी प्रोडक्ट्स की विशाल श्रृंखला
जब अपने घर का हो सवाल, तो सिर्फ ओसवाल



मूंगफली तेल	कच्ची घानी तेल	रिफाईंड सोयाबीन तेल	रिफाईंड सोयाबीन तेल पाउच	बासमती चावल	ओसवाल चावल	पोहा
चाय पत्ती	इस्ट चाय	देसी खांड	धागा मिश्री	हल्दी पाउडर	मिर्च पाउडर	धनिया पाउडर
जीरा	सोया चंक्स	मैज स्टार्च पाउडर	सैधा नमक	काला नमक	मूंग दाल	हरी मूंग दाल
उड़द धुली दाल	तूर दाल	चना दाल	काबुली चना	समभर मसाला	चना मसाला	रायता मसाला
चाट मसाला	गरम मसाला	पाव भाजी मसाला	अल्कलाइन वॉटर	ओसवाल सोप	व्हाइट सोप	मल्टीकलर सोप
वॉशिंग पाउडर	डिटर्जेंट पाउडर	डिटर्जेंट लिक्विड	डिशवॉश लिक्विड	डिशवॉश टब	बाथ सोप	ग्लिसरिन बाथ सोप
लिक्विड हैंड वॉश	शॉवर जैल	ग्लास क्लीनर	टॉयलेट क्लीनर	पशु आहार	हैप्पी टच फ्लोर वाइपर	फूल झाड़ू
फ्लोर क्लीनर	अगरबत्ती धूपबत्ती	नेपथलीन बॉल्स	पशु आहार	हैप्पी टच फ्लोर वाइपर	फूल झाड़ू	फूल झाड़ू

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राष्ट्रपति के प्रश्न तीन के उत्तर में संविधान पीठ ने माना कि राज्यपाल का function justiciable mandamus नहीं है फिर Mandamus जारी करने के निदेशन से कोर्ट स्वयं ही संकट में आ सकती है

कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु राज्य की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये विधेयकों (बिलों) पर निर्णय लेने की सीमा तय की थी। संविधान के सम्बन्धित प्रावधानों में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 200 व 201 की सही व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 कानूनी बिन्दुओं पर राय मांगी। मूल प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में माना कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है।

भारत के संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान भिन्न हैं। प्रारम्भ में ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों ही संवैधानिक प्रमुख रबर स्टाम्प की तरह अपना काम करेंगे; किन्तु समय ने यह सिखा दिया कि ऐसा सोचना सही नहीं था। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 एवं 55 की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है और राज्यपाल (गवर्नर) की नियुक्ति अनुच्छेद 155 की प्रक्रिया से राष्ट्रपति करते हैं। दोनों ही संवैधानिक प्रमुखों को कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 154, 161, 163 व 166 उन्हें कार्यपालिका के अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 168, 158, 200, 201, 213 व अनुच्छेद 174 उन्हें विधायिकका के अधिकार देते हैं। जजों की संविधान पीठ ने अर्थात् सीजेआई गवर्इ, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस चंद्रकर व जस्टिस नरसिम्हा ने अपनी राय एक सुरू में दी है। अनुच्छेद 200 की जो विशद व्याख्या की गई है वह अद्भुत व प्रशंसनीय है। सोलोसिटर जनरल तुषार मेहता के शब्दों में वह ज्ञानवर्धक है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपित सिब्बल ने निर्णय को विवेकपूर्ण व विचारशील बताया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान पीठ ने यह माना कि खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 08 अप्रेल, 2025

जुटिपूर्ण था, जिसमें खण्डपीठ ने राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिये समय सीमा तीन माह तय की थी। इसी फैसले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिन्दुओं पर राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न 1 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत

राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प हैं वे मंजूरी दें, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें या पुनः विचार के लिये टिप्पणी के साथ विधान मण्डल को लौटा दें। उनके पास बिल रोकने का विकल्प नहीं है। प्रश्न 2 के उत्तर में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद में ऐसी कोई बाध्‍यता नहीं है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सला लेवें। प्रश्न 3 के उत्तर में संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के विवेक प्रयोग की समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती; किन्तु संविधान पीठ ने इस मत की अभिव्यक्ति करते हुये भी यह कह दिया कि यदि लम्बे समय तक, अस्पष्ट निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने पर कोर्ट विचार कर अपना निर्देश दे सकती है। संविधान पीठ ने अपने निर्णय (राय) दिनांक 20.11.2025 के पेरा 165 में उपरोक्त कथन को निम्नलिखित रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया है :–

“165.3: The discharge of the Governor’s function under Article 200, is not justiciable. The Court cannot enter into a merits review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite — the Court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time period, without making any observations on the merits of the exercise of his discretion.”

संविधान पीठ ने एक ओर तो विधेयकों पर राज्यपाल से समय सीमा पर मंजूरी प्राप्त न होने पर स्वतः मंजूरी (Deemed Assent) की संविधान की भावना के विपरीत और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध माना है। दूसरी ओर उपरोक्त पेरा 165.3 में जो भावना अभिव्यक्त की है वह प्रश्न एक के उत्तर पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। सब कुछ कहने और स्पष्ट करने पर भी मूल प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही दिखाई देता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कोर्ट की अनिश्चितकाल अथवा अस्पष्ट बात वाली सलाह पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट करता है कि बिल के वापस बन जाने के बाद judicial Adjudication के सिद्धान्त लागू होते हैं, इससे पूर्व राज्यपाल के विवेकपूर्ण निर्णयों पर कोर्ट का दखल स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 200 व 201 के प्रावधानों की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वह सरसम्मत में ज्ञानवर्धक है, और स्पष्ट करती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को केवल वे विकल्प प्राप्त हैं जिनका उल्लेख प्रश्न 1 के उत्तर में दिया गया है। समय उपाय या deemed asscnt का सिद्धान्त अनुच्छेद 200 की शब्दावली में संशोधन करना होगा, जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के प्रयोग के बिना नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा राष्ट्रपति पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के बाद, अब केवल यह विकल्प कार्यपालिका के पास है कि संविधान में यशोचित संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र ही किया जावे और इस उलझी हुई स्थिति से देश को मुक्ति दिलाई जावे। जनहित व देशहित में यह सही मार्ग है।

हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केन्द्र में केन्द्रीय सरकार है और राज्यों में राज्य की सरकारें। हम एक लोकतान्त्रिक गणराज्य हैं। केन्द्र और राज्यों में अलग–2 राजनीतिक पार्टियों की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अधिक होती है। इनमें सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। हमारे संवैधानिक प्रमुख जैसे प्रेसीडेंट व गवर्नर केवल मात्र शोभा के पात्र अथवा रबर स्टाम्प मात्र नहीं हैं। उनकी भूमिका का अपना ही महत्व है उन्हें विवेक व संतुलन के आधार पर अपना कर्त्तव्य पालन करना होता है तथा अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करना है, उसकी पालना करना है। संविधान पीठ ने संवैधानिक प्रमुखों की स्वतंत्रता का अक्षुण्णता प्रदान की है। केन्द्र और राज्य में विभिन्न राजनीतिक मतवालगुम्वियों की सरकारों में आपसी टकराव देखने को मिल रहे हैं, उनमें आपसी सन्तुलन रखना जहां आवश्यक है वहीं बहुत ही नाजुक भी है। अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते समय यह तो कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है, किन्तु यह कह दिया कि अनिश्चितकाल तक निर्णय को रोकना जाना भी उचित नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट का दखल संविधान की गतिशीलता के लिये आवश्यक है, इस प्रकार संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को गतिरोध के चक्करों में फंसेने से बचाने का प्रयत्न किया है। लोकतंत्र की गतिविधियों में चैक व बेलेंस होना आवश्यक है ताकि शक्ति का संचालन में केन्द्रीकरण का खतरा न हो सके। संविधान पीठ ने अपने साहसिक, ज्ञानवर्धक तथा प्रतिभाशाली निर्णय और भविष्य की सुरक्षा के लिये अपनी कलात्मक अनिश्चितकारी टिप्पणी से राहत तो देती; किन्तु अपने स्वंय के लिए एक बड़ी आफत को भी जन्म दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वंय अनुच्छेद 21 में शब्द ‘स्पर्मि’ को व्याख्या करते हुये माना है कि स्पर्म यानी जीवन की गरिमा के लिये न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित होना आवश्यक है, किन्तु देश के नागरिकों को त्वरित न्याय से सर्वथा वंचित दिखाई देते हैं। न्यायालय के प्रत्येक व्यवहार में विलम्ब हो रहा है। वर्षों से मुकदमें लम्बित हैं। फैसलों ही इंतजार ही में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जानमत की अर्जियां तक फैसलों की प्रतीक्षा में दिखाई देती है। जेल में सजा काट रहे कैदियों की अपील, सजा समाप्ति तक निर्णित नहीं होती। सिविल के मुकदमों का निर्णय पोतों के जीवन में भी हो जायेगा, इसकी सम्भावना नहीं है। न्याय सुलभ भी नहीं है और न्याय मंहगा भी बहुत है। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की फीस लाखों रूपये प्रति पेस्री तक है।

न्याय त्वरित नहीं है, सही है; किन्तु न्याय के सुलभ तथा शीघ्र निस्तारण के लिये न्यायालय कोई कारगर कदम भी नहीं उठा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट का कार्य पुराने नियमों के अनुसार ही हो रहा है। नये रूल बनाने में ही वर्षों का समय लगने के बाद भी, लागू तक नहीं किये गये हैं। डिजिटलाईजेशन का उपयोग व प्रयोग कोई संतोषजनक गति नहीं पा सका है।

संविधान की पीठ ने तमिलनाडू के केस के सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा पूछे गये 14 प्रश्नों का उत्तर special reference no.1of 2025 में संविधान पीठ ने दिनांक 20.11.2025 को दिया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में पेरा nंo 165.3 में कहा है कि न्यायालय को उन परिस्थितियों जिनका उल्लेख ऊपर कहा गया है कोर्ट सीमित mandamus जारी कर सकती है। अतः प्रश्न उठाय़ा जा सकता कोर्ट के कार्य में विलम्ब के विषय में कितनी mandamus के हेतु याचिकायें पेश होंगी सोचकर ही सिर चकरा जायेगा।

Sir का प्रश्न संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से सम्बन्ध रखता है, जिसे निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिये अनुच्छेद 324 में दिये हैं अर्थात् इस विशेष पर चुनाव आयोग का निर्णय, न्यायिक समीक्षा से परे है। यदि हम संविधान पीठ के उत्तर की पृष्ठभूमि पर उसे लागू करें तो सम्भव है सभी याचिकायें justiciable नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुच्छेद 329 में वर्जन है।

सत्यमेव जयते! –अतिथि सम्पादक
पानाचन्द्र जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट



अलका सक्सेना

राजस्थान आज अपने विकास यात्रा के उस दौर में है, जहां सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं रहीं, बल्कि वे प्रगति, समृद्धि और सुशासन की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सड़कों के व्यापक नेटवर्क को विस्तार देने, गुणवत्ता सुधारने और सुगमता बढ़ाने का जो अभियान शुरू किया है, उसने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नई गति प्रदान की है। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर गांवों की गलियों तक, हर दिशा में विकास का पहिया गति पकड़ चुका है।
राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 24,976 करोड़ की राशि व्यय कर 36,140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर उल्लेखनीय

कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यह सरकार के उस विजन का परिणाम है जिसमें हर नागरिक तक सुगम, सुरक्षित और तेज़ आवागमन की सुविधा पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़कों के विकास हेतु 12,391 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 28,600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए 14,816 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों ने न केवल ग्रामीण अंचलों की काया पलट दी है, बल्कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। अब तक 1,564 गांव और बसावटें सड़कों से जुड़ चुकी हैं। साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की ‘मिसिंग लिंक’ सड़कों के लिए 1,328 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे पहले से कटे या दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की राह खुली है।

इसी तरह, 327 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब गांव केवल खेती तक सीमित नहीं, बल्कि तेज़ी से विकास के केंद्र बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 22 माह से अधिक के कार्यकाल में राज्य राजमार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

जेठानी देवराणी भी थीं। निक्की को सात साल का एक बेटा भी है। कहा जा रहा है कि निक्की को उसके बच्चे के सामने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। बच्चे ने भी पुलिस को बयान दिया है कि मम्मा को पापा ने लाट्टर से जला दिया। यह सब जब हो रहा था तब निक्की की सास भी अपने बेटे का साथ दे रही थीं। निक्की की बड़ी बहन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर उसे भी मारा पीटा गया। बड़ी बहन ने बताया कि निक्की के साथ देहेज को लेकर अक्सर पार पीट होती थी। शादी के समय लड़के वालों की हर फरमाईश पूरी की गई और शादी के बाद भी अक्सर उनकी मांग आती रही जिसे निक्की के माता पिता ने किसी भी तरह हिंसा और देहेज के मामले से 35 लाख रुपये लाने की बात कही जा रही थी। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले की जहां सरकारी स्कूल की एक व्याख्याता ने अपनी तीन साल की मासूम और अबोध बच्ची को गोले में बिठाकर अपने को आग के हवाले कर दिया। उस बच्ची को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां उसे गोद में क्यों बिठा रही थीं। संजु के पिता ओमपाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए लिखा है कि संजु को देहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कार के अलावा भी उनकी बहुत सी मांगें पूरी की थीं। लेकिन निक्की और मांगों की सूची खत्म नहीं हो रही थी और इसके लिए संजु को प्रताड़ित किया जाता था। उनका कहना है कि बच्ची के जन्म के बाद स्थितियां और खराब हो गई थीं। पुलिस को भी संजु का

यूरिया खाद लेने किसानों की भीड़ उमड़ी

उदयपुर, (का.सं.)। उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक में यूरिया खाद को लेकर भीड़ रही। वहां सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया। खाद को लेकर लोगों को काफी परेशानियां हुई। मावली उपखंड के थामला गांव में थामला ग्राम

राशिफल 28 नवम्बर 2025

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम सम्वत 2082, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 2.50 तक, व्याघात योग गिन 11.05 तक, विष्टिकरण दिन 12.23 तक चन्द्रमा कुम्भ राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति – सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-वृश्चिक, बुध-तुला, गुरु-कर्क, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में संचार करेगा।
रवियोग रात्रि 2.50 से आरम्भ होगा। भद्रा दिन 12.23 तक रहेगी। आज शनि मार्गी प्रात 9.25 पर होगा। आज दुर्गाष्टमी, पंचक है।
श्रेष्ठ चौघडिया – चट – सूर्योदय से 8.19 तक, लाभ अमृत 8.19 से 10.56 तक, शुभ 12.15 से 1.33 तक, चट 4.10 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल – 10.30 से 12.00 तक, सूर्योदय 7.00 सूर्यास्त 5.29

सरकार के विजन के अनुरूप 8,194 करोड़ की लागत से 6,249 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों का विकास पूरा किया जा चुका है, जबकि 2,547 करोड़ की लागत से 8 राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, जिला मुख्यालयों से संपर्क को सुगम बनाने के लिए 5,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। इसका लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं की सहज पहुंच के रूप में दिखाई दे रहा है। डबल इंजन सरकार की नीतियों के अनुरूप राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। अब तक 600 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि 457 किलोमीटर सड़कों पर कार्य प्रगति पर है।

रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 10 आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) और 14 आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं 33 आरओबी और 14 आरयूबी पर कार्य जारी है। इसके साथ ही, 11 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 15 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। इन संरचनाओं ने न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूती दी है, बल्कि यात्रियों का समय और ईंधन दोनों की बचत भी सुनिश्चित की है। नवीनमत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 तक राजस्थान का

के उद्देश्य से 10 आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) और 14 आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं 33 आरओबी और 14 आरयूबी पर कार्य जारी है। इसके साथ ही, 11 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 15 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। इन संरचनाओं ने न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूती दी है, बल्कि यात्रियों का समय और ईंधन दोनों की बचत भी सुनिश्चित की है। नवीनमत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 तक राजस्थान का

कूल सड़क नेटवर्क 3,17,121 किलोमीटर तक पहुंच गया है। सड़क घनत्व अब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 92.66 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। यह दर्शाता है कि राज्य के हर हिस्से में कनेक्टिविटी और पहुंच में गुणात्मक सुधार हुआ है।

राज्य में कुल 39,408 गांव अब सड़कों से जुड़े हैं। वहीं 47 राष्ट्रीय राजमार्ग और 23 राज्य राजमार्गों के उच्च गति यात्रा के लिए उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 10,790 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 17,376 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 2,06,318 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें सक्रिय हैं।

यह नेटवर्क न केवल राजस्थान के आंतरिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों से निर्बांध संपर्क भी सुनिश्चित कर रहा है। राजस्थान की सड़क नीति केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दृष्टिकोण व्यापक है – यह समाज विकास का माध्यम बन चुकी है। बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों के लिए आधारशिला सिद्ध हो रही हैं। गांवों से मंडियों तक उत्पादों की सुगम आवाजाही से किसानों की आमदनी बढ़ी है। उद्योगों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि सड़कें विकास की समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेडियों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल किताबी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियों अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को मजबूत दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाने

आत्महत्या नोट मिला है जिसमें उसने ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संजु की आत्महत्या के समय घर पर कोई नहीं था।

दोनों ही दुर्घटनाओं से मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। निक्की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थीं। वह अपना पालर चलाती थीं।संजु सरकारी नौकरी कर रही थी। दोनों ही परिपक्व उम्र की थीं।फिर भी वे देहेज के लिए अत्याचार क्यों सह रही थीं? निक्की और संजु के माता पिता क्यों बार बार लड़के वालों की देहेज को मांग को पूरा कर रहे थे? उन्होंने उन्हें अपने पास वापस क्यों नहीं बुला लिया? क्यों नहीं निक्की और संजु या उनके पीहर वालों ने घरेलू हिंसा और देहेज के मामलों में पुलिस को शिकायत की? अब जबकि निक्की और संजु की मौत हो गई है और उनके पीहर वाले देहेज का मामला दर्ज करा रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी देहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि देहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजु के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आवाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल

समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेडियों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल किताबी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियों अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को मजबूत दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाने

आत्महत्या नोट मिला है जिसमें उसने ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संजु की आत्महत्या के समय घर पर कोई नहीं था।

दोनों ही दुर्घटनाओं से मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। निक्की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थीं। वह अपना पालर चलाती थीं।संजु सरकारी नौकरी कर रही थी। दोनों ही परिपक्व उम्र की थीं।फिर भी वे देहेज के लिए अत्याचार क्यों सह रही थीं? निक्की और संजु के माता पिता क्यों बार बार लड़के वालों की देहेज को मांग को पूरा कर रहे थे? उन्होंने उन्हें अपने पास वापस क्यों नहीं बुला लिया? क्यों नहीं निक्की और संजु या उनके पीहर वालों ने घरेलू हिंसा और देहेज के मामलों में पुलिस को शिकायत की? अब जबकि निक्की और संजु की मौत हो गई है और उनके पीहर वाले देहेज का मामला दर्ज करा रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी देहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि देहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजु के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आवाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल

समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेडियों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल किताबी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियों अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को मजबूत दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाने

आत्महत्या नोट मिला है जिसमें उसने ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संजु की आत्महत्या के समय घर पर कोई नहीं था।

दोनों ही दुर्घटनाओं से मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। निक्की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थीं। वह अपना पालर चलाती थीं।संजु सरकारी नौकरी कर रही थी। दोनों ही परिपक्व उम्र की थीं।फिर भी वे देहेज के लिए अत्याचार क्यों सह रही थीं? निक्की और संजु के माता पिता क्यों बार बार लड़के वालों की देहेज को मांग को पूरा कर रहे थे? उन्होंने उन्हें अपने पास वापस क्यों नहीं बुला लिया? क्यों नहीं निक्की और संजु या उनके पीहर वालों ने घरेलू हिंसा और देहेज के मामलों में पुलिस को शिकायत की? अब जबकि निक्की और संजु की मौत हो गई है और उनके पीहर वाले देहेज का मामला दर्ज करा रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी देहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि देहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजु के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आवाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल

समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेडियों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल किताबी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियों अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को मजबूत दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाने

आत्महत्या नोट मिला है जिसमें उसने ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संजु की आत्महत्या के समय घर पर कोई नहीं था।

दोनों ही दुर्घटनाओं से मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। निक्की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थीं। वह अपना पालर चलाती थीं।संजु सरकारी नौकरी कर रही थी। दोनों ही परिपक्व उम्र की थीं।फिर भी वे देहेज के लिए अत्याचार क्यों सह रही थीं? निक्की और संजु के माता पिता क्यों बार बार लड़के वालों की देहेज को मांग को पूरा कर रहे थे? उन्होंने उन्हें अपने पास वापस क्यों नहीं बुला लिया? क्यों नहीं निक्की और संजु या उनके पीहर वालों ने घरेलू हिंसा और देहेज के मामलों में पुलिस को शिकायत की? अब जबकि निक्की और संजु की मौत हो गई है और उनके पीहर वाले देहेज का मामला दर्ज करा रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी देहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि देहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजु के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आवाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल

समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेडियों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल किताबी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियों अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को मजबूत दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की

जयपुर रिंग रोड के उत्तरी हिस्से के निर्माण की कार्यवाही तीव्र करें : भजनलाल शर्मा

प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के जमीन अधिग्रहण को शीघ्र प्रारंभ करें : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत व सुरक्षित बनाने एवं विस्तार देने के लिए डबल इंजन की सरकार बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों

- प्रदेश के रोड नेटवर्क की मजबूती व विस्तार हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री**

को निर्देश दिए कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए आपसी समन्वय से समय-सीमा में प्रगतिरत परियोजनाओं को पूरा किया जाए। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एनएचएआई के कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण के संबंध में एनएचएआई को निर्देश दिए कि इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक लेकर एनएचएआई के कार्यो की समीक्षा की।

जाए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने के लिए जमीन अधिग्रहण के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के संबंध में निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर जयपुर से जुड़े महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के गोदाम और वेयरहाउस विकसित करने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने 200 फीट चौड़ाह पर एनएचएआई द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यो को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। शर्मा को

जयपुर-ब्यावर-पचपदरा, जयपुर-किशनगढ़, चितौड़गढ़ बायपास और अलवर-भरतपुर-आगरा सड़क निर्माण के विकास के संबंध में एनएचएआई के अधिकारियों ने जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग और एनएचएआई के अधिकारी उपस्थित रहे।

तालाबी भूमि को बारानी भूमि दिखाने पर तहसीलदार सहित तीन कार्मिक निलम्बित

सांगानेर के पालड़ी परसा गांव का मामला

जयपुर, (कासं)। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनियमितता और गड़बड़ी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

इसी क्रम में तहसील सांगानेर के पालड़ी परसा गांव में पेटा तालाबी भूमि को बंजर अथवा बारानी भूमि के तौर पर किस्म परिवर्तन करने के प्रकरण को राज्य सरकार ने बेहद गंभीर अनियमितता माना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में प्रकरण में संलिप्त

- अनियमितता के विरुद्ध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति**

तहसीलदार सहित तीन कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रकरण में राजस्व मंडल ने सांगानेर तहसीलदार कार्तिकिय लाटा को त्वरित प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं, जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर पटवार हलका देवेलिया की हाल पटवारी नयनसी वर्मा एवं पटवार हलका

देवेलिया के तत्कालीन पटवारी श्री हाकिम सिंह गुर्जर को पूरे प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर त्वरित प्रभाव निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी लापरवाही, गड़बड़ी या अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोषी कार्मिकों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

किसानों को निर्बाध उर्वरक आपूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध : किरोड़ी

जयपुर। राज्य के कृषकों को समयबद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल ने पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में मीडिया से रूबरू होकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। राज्य सरकार किसानों को उर्वरकों की निर्बाध रूप से पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हो कर प्रयासरत है तथा जिलों में यूरिया व डाइपो की कमी की स्थिति बनी है वहां तत्काल प्रभाव से पूर्ति करवायी जा रही है।

डॉ. किरोड़ीलाल ने बताया कि प्रदेश में समय पर हुई पर्याप्त वर्षा तथा अक्टूबर माह में दो बार असमायिक वर्षा से भूमि में नमी की उपलब्धता बढ़ी, जिससे कृषकों द्वारा अग्रिम बुवाई में तेजी

आई। इस वर्ष 26 नवम्बर तक गत वर्ष की तुलना में 9 लाख हैक्टेयर अधिक क्षेत्र में बुवाई की जा चुकी है। वहीं तिलहनी फसलों में 34 लाख हैक्टेयर एवं खाद्यान्न फसलों में 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रथम सिंचाई के साथ यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप यूरिया की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

कृषि मंत्री ने बताया कि रबी सीजन के पहले दो लाखों-अक्टूबर व नवम्बर-में 7.53 लाख मैट्रिक टन की मांग के विरुद्ध 9.15 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 24 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति जारी है तथा आगामी दो दिनों में 31 हजार मैट्रिक टन यूरिया और उपलब्ध होने से माह के अंत तक कुल उपलब्धता 9.70 लाख मैट्रिक टन से अधिक हो जाएगी।

5.44 करोड़ की बकाया लीज प्रकरण में नीमराना डवलपर्स को जेडीए ट्रिब्यूनल से नहीं मिला स्थगन

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) ट्रिब्यूनल ने मैसर्स नीमराना डवलपर्स को 5.44 करोड़ रु. की बकाया लीज राशि जमा नहीं करवाने के मामले में अंतरिम स्टे देने से इनकार कर दिया है।

इस प्रकरण में बिल्डर की ओर से अधिवक्ता एस.एस.सोलंकी ने दलील दी थी कि, उनके मुवक्किल ने एयरपोर्ट प्लाजा में भूखंड संख्या 1 की 8236.47 वर्गमीटर जमीन जेडीए से नीलामी में खरीदी थी। इस जमीन पर बनाए गए 207 फ्लैट्स में से उसने 165 फ्लैट्स लोगों को बेच दिए हैं, 25 फ्लैट्स पर इंटीरियर का काम चल रहा है। ऐसे में उससे सिर्फ उन्हीं फ्लैट्स की लीज राशि वसूली जानी चाहिए, जो उसके पास बचे हुए है। परंतु गत 14

- जयपुर विकास प्राधिकरण ने गत 14 नवंबर को बिल्डर को नोटिस थमाकर कुर्की की चेतावनी दी थी**

नवंबर 2025 को जेडीए ने डवलपर को नोटिस देकर 5.44 करोड़ रुपए की बकाया लीज राशि जमा करवाने का नोटिस दिया और संपत्ति कुर्क की चेतावनी दी। जबकि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग ने 19 फरवरी 2020 को आदेश जारी किया था कि, भवन निर्माता द्वारा फ्लैट्स को अलग-अलग लोगों को बेचने के बाद क्रेता द्वारा ही लीज राशि चुकायी जायेगी।

बिल्डर ने वर्ष 2016 में भूखंड आवंटन से लेकर वर्ष 2021 तक की बकाया लीज राशि जेडीए को जमा करवा दी थी, परंतु जेडीए प्रशासन अब यह संपूर्ण राशि डवलपर से लेना चाहता है।

बिल्डर की इस दलील का विरोध करते हुए जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि, यह पूरी कार्रवाई भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 64-ए के तहत की जा रही है। ऐसी स्थिति में जेडीए ट्रिब्यूनल के पास हस्तगत मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वहीं बिल्डर ने यह भी नहीं बताया है कि उसने 165 फ्लैट्स कब-कब और किस तारीख पर लोगों को बेचे है। ऐसे में क्रेताओं पर लीज राशि की गणना किस प्रकार हो सकेगी।

बीकानेरी रसगुल्ला एवं नमकीन भंडार में लगी आग



दमकलकर्मियों ने जेसीबी मशीन से शटर तोड़कर आग पर काबू पाया।

जयपुर। श्याम नगर थाना इलाके में स्थित अजमेर रोड पर बीकानेरी रसगुल्ला,नमकी भंडार में गुरुवार सुबह अनामक से भीषण आग लग गई। जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस भीषण आग ने पास ही मे स्थित एक मैरिज गार्डन को भी अपने आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि की लपटे इतनी तेज थी कि दूर -दूर तक दिखाई दे रही थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को साइड में हटाया और मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी। दमकल विभाान की करीब 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तीन -चार घंटे में आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टि से आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच -पड़ताल

करने में जुटी है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल दमकलकर्मियों ने पाईयों को अंदर ले जाकर आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए काफी थोर आजमाईश की। जिस दुकान में आग लगी थी उसका शटर बंद था। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने दुकान मालिक का ईंतजार किए बिना ही जेसीबी मीके पर बुलवाई और शटर तोड़कर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बिना किसी जनहानि के आग पर कुछ ही घंटों में काबू पा लिया गया। लेकिन इस आग में मैरिज गार्डन और नमकीन भंडार में लाखों रुपयों का सामान का भी भेंट चढ़ गया। गनीमत रही कि मौके से 3-4 एलपीजी गैस सिलेंडर समय रहते हटा दिए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

शातिर वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर वाहन चोर को पकड़ा है और उसके पास से एक चोरी का दुपहिया वाहन भी जब्त किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि नाहरगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाले शातिर वाहन चोर 38 वर्षीय रामू मीणा निवासी दोसा हाल खानाबदोश नाहरगढ़ जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से एक चोरी का दुपहिया वाहन (स्कूटी) भी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित नशे का आदी है। जो नशे का शौक पूरा करने के लिए दुपहिया वाहनों की रैकी कर चुराता था।

कॉमर्स कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया



जयपुर (कासं)। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉमर्स कॉलेज में गुरुवार को नवनिर्मित भवन “ब्लॉक बी” का लोकार्पण राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने किया। समारोह की शुरुआत अतिथि सत्कार, राष्ट्रगान एवं विश्वविद्यालय के कुलागीत से हुई। राज्यपाल ने कहा कि, शिक्षा में स्थापत्य कला का महत्व होता है। इस दृष्टि से वाणिज्य महाविद्यालय (कॉमर्स कॉलेज) के नवनिर्मित भवन का अत्यन्त महत्व है। वाणिज्य, व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें बैंकिंग, वित्त, विज्ञापन, प्रबन्धन आदि आते हैं। वाणिज्य से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तथा ध्यान से काम करने की आदत बनती है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डाला तथा कहा कि 1835-36 में अंग्रेजों द्वारा दी गयी शिक्षा नीति में

बदलाव कर अब शिक्षा में भारतीयता पर जोर दिया जा रहा है। विनोबा भावे का नामोल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी के साथ ही भारतीय शिक्षा नीति अपनानी चाहिए थी इसके साथ ही उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गयी शिक्षा नीति की आलोचना भी की। उन्होंने उद्बोधन में प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्रों नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने विश्वविद्यालय को इनसे भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। प्राचीन ज्ञान परम्परा पर बल देते हुए उन्होंने मनोज कुमार, अभिनीत फिल्म पुरब-पश्चिम के गाने “जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनियां को तब गिनती आयी“ के माध्यम से कहा कि हमने अपनी संस्कृति और शिक्षा पद्धति से पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है।

वाईएल फार्मा की एक दवा नकली

जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने वाईएल फार्मा की एक दवा को नकली घोषित किया है। साथ ही, पूरे राज्य में इस दवा के उपयोग एवं विक्रय पर निगरानी के लिए अलर्ट नोटिस जारी किया है। आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि वाईएल फार्मा की दवा लिबोसिस्ट्रीजिन

- औषधि नियंत्रण विभाग ने इस कंपनी की अन्य दवाओं के भी नमूने लेने के लिए निर्देश**

डाइहाइक्लोराइड एण्ड मोनोटेल्ब्यूकास्ट सोडियम टेबलेट के दो स्थानों से नमूने लिए गए थे। इन नमूनों को जांच के लिए राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में भेजा गया था, जहां जांच में इस दवा में एक साल्ट मोनोटेल्ब्यूकास्ट शुन्य पाया गया है। इस आधार पर इस दवा को नकली घोषित किया है। औषधि नियंत्रक, प्रथम अजय फाटक ने बताया कि समस्त सहायक औषधि नियंत्रण एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों को अलर्ट नोटिस जारी कर इस दवा के उपयोग एवं विक्रय पर पूरी निगरानी रखने एवं अन्य दवाओं के भी नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं।

24 तीर्थकरों ने मानव जाति को दिखाया सही मार्ग : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परम पूज्य सुंदर सागर महाराज ज्ञान और अहिंसा का दीपक जलाते हुए समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और करुणा का अद्भुत समन्वय है। हमारी सरकार सभी धर्मों के विकास और संरक्षण के लिए समर्पित है। उन्होंने आमजन से आन्धान किया कि वे जैन मुनियों के उपदेशों को न केवल सुनें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारें। शर्मा गुरुवार को सांगानेर कैम्प कार्यालय में आयोजित आचार्य सुंदर सागर महाराज की दिव्य देशना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इस धर्म के 24 तीर्थकरों ने समय-समय

पर मानव जाति को सही मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ‘अहिंसा परमो धर्म’ है। ये एक वाक्य नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवन दर्शन है। आज पूरी दुनिया हिंसा से जूझ रही है और जैन धर्म का यह संदेश वर्तमान परिवेश में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी संतो की पद वेदना करते हुए उनका हाथ धामे एसएफएस मानसरोवर स्थित आदिनाथ मंदिर से सांगानेर कैम्प कार्यालय में कार्यक्रम में लेकर आए। इस दौरान मार्ग में पुष्प वर्षा एवं बैड वादन कर उनका स्वागत-अभिन्दन किया गया। कार्यक्रम में शर्मा को ‘मातृ भू सेवक’ की मानद उपाधि से अलंकृत भी किया गया।

सार-समाचार कलेक्टर ने किया 3 ईआरओ का सम्मान



जयपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने गुरुवार को जिले के तीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को सम्मानित किया। जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शाहपुर निर्वाचक पदाधिकारी संजीव कुमार खेदर, ददू निर्वाचक पदाधिकारी रमेश कुमार एवं बस्सी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी डॉ. गरिमा सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बीएलओ से संवाद के दौरान उन्होंने न केवल उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की मुक्तकंठ से सराहना की, बल्कि यह भी कहा कि उनकी यह प्रतिबद्धता पूरे जिले के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने अनुभव, ऊर्जा और कार्यकुशलता से अन्य साथियों को प्रेरित कर उन्हें भी लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन दें, ताकि पूरे जिले में पुनरीक्षण अभियान की गति और अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली रूप में आगे बढ़ सके। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना कार्य प्रगति पर है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी निरंतर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि 36 लाख 75 हजार 806 यानी 76.03 फीसदी से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

डॉ. अखिल शुक्ला को मिला अवार्ड



जयपुर। भारत स्काउट व गाइड संगठन द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान सिक्वर एलीफैंट अवार्ड से राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य आयुक्त एवं अधिवक्ता डॉ. अखिल शुक्ला को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश राजभवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। समाज सेवा एवं रक्तदान जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. शुक्ला देशभर में एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। डॉ. शुक्ला वर्ष 1989 से लगातार रक्तदान जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में राजस्थान वॉलंटरी ब्लड डोनर्स सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं। इसके साथ ही वे हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय के आजीवन सीनेट सदस्य, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। वे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उधर, भारत स्काउट व गाइड द्वारा लखनऊ में आयोजित भव्य जन्मूरी में हजारों युवा अनुशासन के साथ सहभागिता कर रहे हैं। जन्मूरी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर चुके हैं, जबकि समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाग लेने की संभावना है।

बैडमिंटन लीग में मुकाबला जारी



जयपुर। स्पोफिट अकेडमी में 21 नवंबर से जारी डॉक्टर्स बैडमिंटन लीग में 26 नवंबर को खेले गए टीम इवेंट मुकाबलों में, बॉयज वर्ग में ऑंच टाइटन्स ने शॉल्डर एंड नी सर्वरी क्लीनिक को हराया। लीग संयोजक डॉ. हरशी भारद्वाज तथा लीग आयोजन अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव ने बताया कि वरिष्ठ वर्ग में मंगमन प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल ने लीग मैच में एचसीजी हॉस्पिटल को 5-0 से हराया। दोनों ही टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कदमदेम ने जय गणपति हॉस्पिटल को 5-0 से हराया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लीग आयोजन सचिव डॉ हनुमान खोजा ने बताया कि किड्स डेंटल टीम ने अपने लीग मैचैज समाप्त कर, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला टीम इवेंट कॉर्डिनेटर प्रेम चौधरी ने बताया कि सम्भव डायनोमेटिक और प्रियंका हाईएनल ने अपने लीग मैच में अपने अपने ग्रुप में 3-3 टाई जीत कर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया।

कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन आज से

जयपुर। किसानों की आय बढ़ाने और सतत कृषि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना की वार्षिक समूह बैठक 28 नवंबर से राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर में होगी। राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागीधर चौधरी, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. एम एल जाट होंगे। बैठक की अध्यक्षता श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोधपूर के कुलपति डॉ पुष्पेंद्र सिंह चौहान करेंगे। इस वार्षिक बैठक में देश के 25 राज्यों में स्थापित अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना केंद्रों के वैज्ञानिक भाग लेंगे। जो कि कृषि प्रणाली, फसल विविधीकरण और संबंधित अनुसंधान गतिविधियों की प्रगति और उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे। तीन दिवसीय आयोजन के दौरान ऑन-स्टेशन एवं ऑन-फार्म अनुसंधानों की प्रगति की समीक्षा, मॉडल वैल्यू चेन विकास, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्रों में संचालित कार्यक्रमों की प्रगति, प्रशासनिक एवं वित्तीय पहलुओं पर विचार-विमर्श, फसल विविधीकरण कार्यक्रम की समीक्षा होगी। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों के हल के लिए भारी दुर्गापुरा में विकसित उन्नत समन्वित कृषि मॉडलस का फील्ड भ्रमण भी आयोजित किया जाएगा। यह वार्षिक समूह बैठक कृषि में संसाधन आधारित प्रणाली को मजबूत बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहन देने तथा सतत एवं लाभकारी कृषि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करेंगी।

आठवीं क्लास के छात्र ने फांसी लगाई

जयपुर। सांगानेर सदर थाना इलाके में गुरुवार को प्राइवेट स्कूल के 8 वीं क्लास के छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतार अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया। वहीं पुलिस ने इस मामले में मर्ग दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी है। थानाधिकारी अर्जुन जैमन ने बताया कि वादिका रोड डेयरी जोड़क में रहने वाली मोक्ष यादव ने अज्ञात कारणों के चलते फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतार अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया। पुलिस पृछताछ में सामने आया है कि मोक्ष यादव हरियाणा का रहने वाला था और अपनी बुआ के पास रह था। प्रताप नगर स्थित जानकी देवी स्कूल में कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने मामले की जानकारी भूतक के परिजनों को दे दी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर में मोक्ष अपने कमरे में था। काफी देर तक जब मोक्ष यादव बाहर हीं आया और कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो उसकी बुआ उसे देखने के लिए कमरे में गई और मोक्ष को फंदे से लटका देख चिल्लाई। चौख-पुकार की आवाज सुन आसपास के पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे। जिसके बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई।



Fur-Free Friday: Championing Compassion Over Fashion

Fur-Free Friday, observed on the day after Thanksgiving, is a global movement dedicated to raising awareness about animal cruelty in the fur industry. On this day, activists and animal lovers unite to advocate for ethical, cruelty-free fashion choices. Through peaceful protests, social media campaigns, and educational drives, the event urges brands and consumers alike to reject real fur and embrace sustainable, humane alternatives. More than a campaign, Fur-Free Friday is a call for compassion, reminding the world that true style never comes at the cost of another creature's suffering.

#SCULPTURE

The Story of an Ancient Roman Goat

The work exemplifies the Roman fascination with both realism and ideal beauty



In the quiet poise of marble, one of the most unexpected stars of ancient Roman sculpture takes shape, a resting goat, captured in stone with both tenderness and vitality. This remarkable piece, on view at the Kimbell Art Museum in the exhibition ‘Myth and Marble: Ancient Roman Sculpture from the Torlonia Collection’, offers an intimate look at how Roman artists, and later, their Baroque admirers, infused even humble creatures with grace and grandeur.

An Ancient Work Re-imagined

Titled ‘Statue of a Resting Goat,’ the sculpture dates to the Imperial Period, Trajanic Era (late 1st century CE). The work exemplifies the Roman fascination with both realism and ideal beauty. Romans often copied and adapted Greek originals, but this piece goes further, blending naturalistic anatomy with serene composure that makes the animal feel almost human in its stillness.

What makes this goat especially intriguing is its dual authorship across time. The body of the statue is ancient Roman, but the head was later reworked and attributed to none other than Gian Lorenzo Bernini (1698-1680), the Baroque master sculptor who brought marble to life with an unmatched sense of motion and emotion. Bernini’s addition bridges two worlds: the classical past and the exuberant Baroque era, showing how Rome’s artistic legacy was never static, but constantly reinterpreted.

The Torlonia Collection

The piece belongs to the Torlonia Collection, one of the most important private collections of ancient sculpture in the world. Assembled by the wealthy Torlonia family in the 18th and 19th centuries, the collection preserves hundreds of Roman masterpieces that have rarely been seen outside Italy, making this exhibition a once-in-a-lifetime opportunity for museumgoers.



The Goat as Symbol

In Roman art, animals were far more than decorative motifs. The goat, in particular, carried symbolic resonance, linked to rustic life, fertility, and the wild god Pan, whose half-goat form embodied the untamed forces of nature. In this sculpture, though, the goat rests, its wildness subdued, its pose calm and contemplative, as if it has found harmony between nature and civilization.

Curatorial Insight

Jennifer Casler Price, senior curator of Asian, African, and Ancient American Art at the Kimbell, notes how such works reveal the deep dialogue between past and present that defines Roman sculpture. “Even something as modest as a resting goat,” she explains, “can show us the Romans’ extraordinary ability to observe, reinterpret, and elevate the natural world.”

Visit ‘Myth and Marble’

“Myth and Marble: Ancient Roman Sculpture from the Torlonia Collection” is on view at the Kimbell Art Museum through January 25. The exhibition gathers over 90 masterpieces, from emperors and gods to animals like this remarkable goat, each one testifying to the enduring power of classical art to speak across millennia.

Ni'mat Khan's garden of triangles



Traditionally, medieval gardens have been viewed as spaces for elite enjoyment, social gatherings, relaxation and exchange of ideas. And this ideology is not only restricted to those enjoying the floral ecstasies of mother nature, but even in the landscape planning. Garden design in the period often employed trends such as astrology, geomancy, magic and numerology to enhance the experience and impact of such sensory spaces. So seriously were these factors regarded that, according to a 16th century text, a massive garden in the kingdom of Ahmednagar (present-day Maharashtra) was redone just because of triangles.

Ni'mat Khan, a courtier under Murtaza Nizam Shah I in the Indian subcontinent's Deccan region, was ordered to construct a garden and a subterranean canal. The noble immediately occupied himself with the task at hand and, according to Tabatabai, a Nizam Shahi historian who wrote about the incident in AD 1576, ‘after a few days, such a garden and edifices were built that the highest paradise melted in the fire of envy.’ The garden was named Farah Bakhsh (Joy Bestowing), adjacent to the Farah Bakhsh Palace.

Farah Bakhsh, however, failed to please the Shah. Historian Firishta writes, “When Murtaza Nizam Shah went to that garden for amusement, it did not appeal to him...he dismissed Ni'mat Khan from the post of superintendent of that garden, and instructed Salabat Khan to pull down the building on which immense sums of money had been spent, and constructed another in its place.” Tabatabai's account adds to this information a small but significant detail, that the structure comprised numerous triangles. But why would the Shia king have such

a violent reaction against a seemingly splendid garden? To understand this, two things are important, first, the knowledge that buildings were as essential to the garden as plants, in both Indic and Persianate cultures, and second requires us to take a small detour to the court of Bijapur ruled by Murtaza's brother-in-law, Ali Adil Shah I.

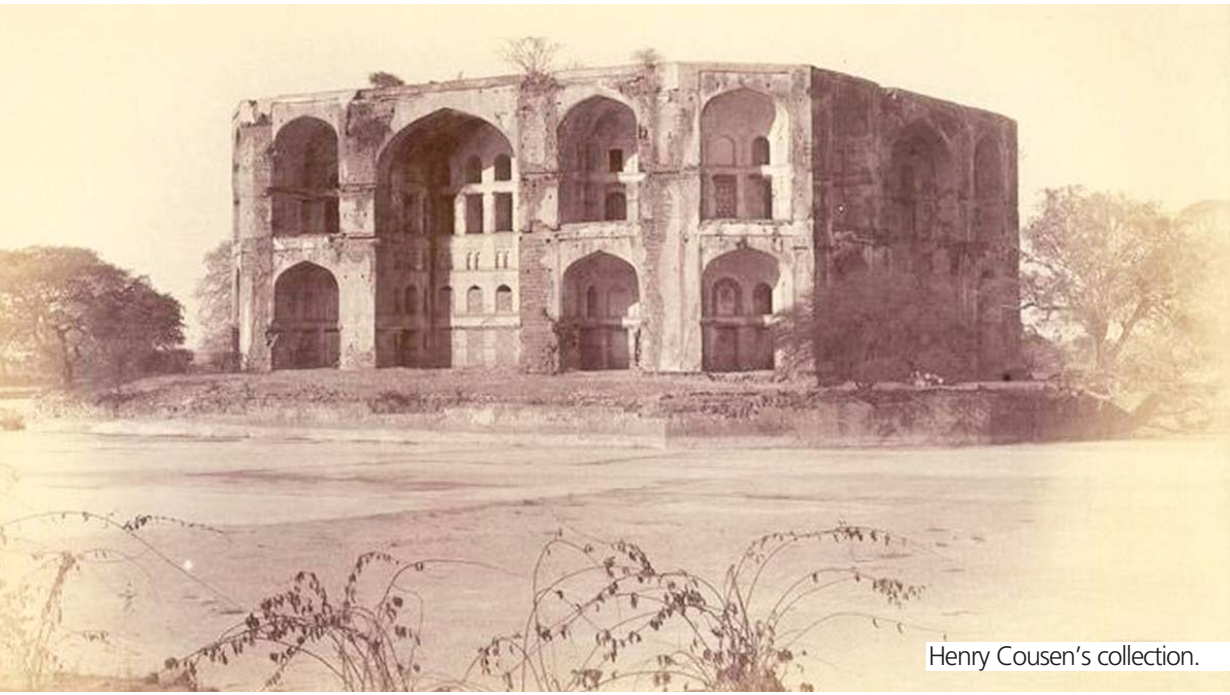
The Bijapuri ruler had written a significant treatise called Nujum al-'Ulum (The Stars of the Sciences). This text had a particular description for Mirrikh (Mars/Mangal), that ‘his buildings are triangular (musallas).’ Anyone worth his salt in medieval India would know that the planet Mirrikh was considered inauspicious in the Indic, Persianate and Hellenistic traditions. So, it's no surprise that Nizam Shah ordered the demolition of a stunning garden upon seeing triangular structures. Interestingly, such astronomical connections weren't restricted to shapes. The 6th century text Brihat Samhita prescribes specific nakshatras (constellations) for planting trees. Dr. S Natesh, who has worked extensively on plants and environment conservation, says, “Some Puranas also prescribe each person born under a specific star to plant a particular tree.”

Turning the globe

Astrology has played a perennial role in medieval gardens, starting from the cycles of planting to pruning and fertilising. Ahmednagar and Bijapur are not the only places where one finds a reference to astrology intersecting with aesthetics in the medieval world. The 17th century masnawi (collection of poems) *Falak al-Buruj* by Ruh al-Amin is also arranged around the two intersecting themes. Turning the globe further, one finds an interplay between iconography and astronomy in examining the sundials decorating the early modern Roman gardens of Villa Aldobrandini of Frascati (Italy). Aside from astrology, the discourse of gardens also pervaded other discourses, such as that of geomancy that informed the elite culture of the Ming dynasty in China, showing its manifestations in both garden design and landscape painting.



The humble administrator's garden (Suzhou) reveals the propensity for geomancy and mathematics in architecture and landscape design.



Henry Cousen's collection.



Meister des Nujūm-al 'Ulūm Manuscripts.



Palatine Chapel cathedral Aachen Gre portion structure.



Astronomical symbolism in the Carolingian period.

#GARDEN



Basilica of San Pietro in Vaticano.

Humble Administrator's Garden (Suzhou), the garden of Wen Zhengming's poems and paintings (15th-16th centuries) and a UNESCO World Heritage Site, reveals the propensity for geomancy and mathematics in architecture and landscape design. Returning to Farah Bakhsh, the site of our contestations, Deccan sultanates' scholar Emma J Flatt argues that a garden could often become the space where the competency of nobles in courtly skills, like garden design and astrology, could be tested or demonstrated. She adds that “Ni'mat Khan's lack of education and low origins is dramatically revealed in the exemplary ethical and didactic space of a garden when he builds a garden ‘made of triangles,’ a garden that by its shape is drawing the influence of the inauspicious planet Mirrikh upon the kingdom of Ahmednagar.” His garden, despite its obvious beauty, was, therefore, unacceptable and, while lacking these qualities, he couldn't be a ‘real’ noble.

Gardens have been significant institutions for the elites of South Asia since the Mauryan times (322-185 BCE). Popular imaginations of medieval gardens, however, constantly conjure up images of symmetrically planned, quadripartite, walled gardens with water channels, the Mughal Charbagh. Early garden sites lacking these features have been overlooked and are poorly preserved as compared to their Mughal or Timurid peers. This has, therefore, necessitated the need to find sources, other than monumental, to study the question of garden traditions of the Deccani kingdoms.

Roots of society and culture Scholars such as Craig Clunas and Dixon Hunt have lit a path away from the rather restricted focus on gardens as physical objects of enquiry. This makes it possible for us to interrogate literary and sculptural sources, aside from archaeological sources, which reveal the history of the garden as a cultural institution that represented the attitudes and practices of the people who patronised, constructed, took care of and experienced these gardens.

According to French historian and critic Hippolyte Taine, a lot can be revealed about the motive and psychology of people through their

literature. Gardens, like literature and paintings, are most indicative of the moment and milieu in which they are borne. The story of Ni'mat Khan's garden of triangles is only one analysis of how the discourses of astrology and magic prevalent in medieval Deccan influenced garden design and practices. Studies into the actual practices of gardens can help rediscover many such sites that contribute significantly to our understanding of the cultural, social, and religious currents of South Asia.

From a few sporadic pieces of news contained in studies of historical nature, we know that, with all probability, the apprentice architect in the field of Byzantine culture had to face the study of the quadrivium, i.e., arithmetic, astronomy, geometry and music. Even if it is not possible to know the degree of depth of knowledge of the various disciplines involved in the training, it is likely that notions of general knowledge were given, useful for dealing with the basic needs already identified by Vitruvius in his study.

Manuela Incerti's Astronomical Knowledge in the Sacred Architecture is the fields of

Deccan sultanates' scholar Emma J Flatt argues that a garden could often become the space where the competency of nobles in courtly skills, like garden design and astrology, could be tested or demonstrated. She adds that “Ni'mat Khan's lack of education and low origins is dramatically revealed in the exemplary ethical and didactic space of a garden when he builds a garden ‘made of triangles,’ a garden that by its shape is drawing the influence of the inauspicious planet Mirrikh upon the kingdom of Ahmednagar.” His garden, despite its obvious beauty, was, therefore, unacceptable and, while lacking these qualities, he couldn't be a ‘real’ noble.

research for architecture Orientation between the ninth and the tenth centuries. Calcidius Macrobius, Martianus Mineus Felix Capella, Boethius, Cassiodorus, Isidorus Hispalensis, the Venerable Bede, Johannes Scotus Erigena and other authors produced an important series of Latin studies. The merit of this phase of scientific culture is that of having given a certain structure to the various disciplines by condensing in the quadrivium, the surviving nucleus of ancient scientific culture. The teaching of these four disciplines is already present in the Carolingian school of thought coordinated by Alcuin (c.830-90) (CISAM 1972; Leonardi 1981; Prova 1974) which directed its attention towards music, astronomy and astrology.

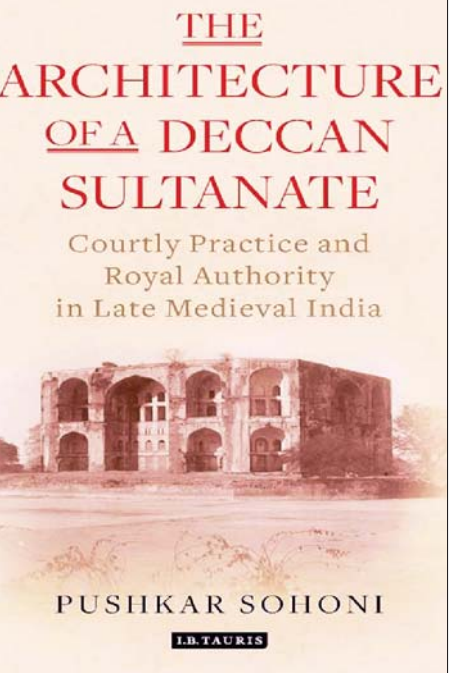
St. Peter's Basilica is a familiar cultural landmark, begun under the patronage of Pope Julius II by the architect Donato Bramante and substantially completed by Michelangelo. Following a common Renaissance practice, a horoscope was produced for the foundation ceremony of the great structure. It suggests several features of Renaissance astrological practice in coordinating



Faria Bagh, Ahmednagar.



Farah Bagh as it stands today in Ahmednagar.



the heavens with the earth. This essay argues that the horoscope published in 1552 is not the original horoscope but, rather, a ‘rectified’ chart made after the church construction has been stalled for nearly forty years; that the date had been chosen according to religious and political dictates, and so, the astrologer(s) had to work with the planetary positions that pertained on 18 April 1506; that the astrologer(s) chose the time of day, a time correctly noted not in the published horoscope but in the diary of Julius's personal secretary, because it coordinated the founding of the basilica with the important horoscopes of its patron and its region; that the primary patron of the basilica was not Julius but, rather, Christ, whose geniture was discussed in astrological texts of this era; that the coordination of the basilica's horoscope with that of Christ simultaneously coordinated the great structure with the thema mundi, the horoscope for the birth of the world; and that several putative horoscopes for Julius II seem related to those of the basilica and of Christ.

rajeshsharma1049@gmail.com

#REMEMBERING

Dr. B.R. Ambedkar's 1955 BBC Interview on Caste and Gandhi

Gandhi advocated for the abolition of untouchability but maintained support for the broader varna system

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, whose ideas and activism laid the foundation for a more just and inclusive India, is remembered always.

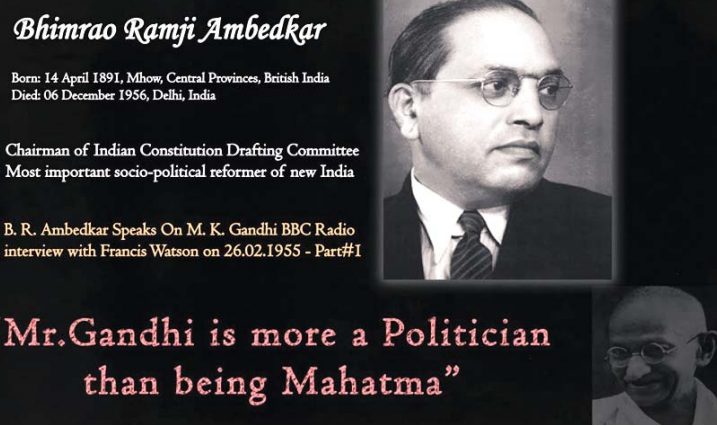
Dr. Ambedkar, born in 1891 into a Dalit family, in what is now Madhya Pradesh, rose from the most marginalized strata of Indian society to become a global voice against oppression and inequality. Ambedkar's life and ideas continue to resonate deeply with millions across the country and beyond. A fierce opponent of the caste system, he dedicated his life to fighting the social, political, and economic exclusion of Dalits, then referred to as ‘untouchables.’ One of the most important records of his thoughts in his own voice is a rare and remarkably candid interview he gave to the BBC in 1955, just one year before he converted to Buddhism and a year before his death.

In this historic interview, Dr. Ambedkar speaks plainly and passionately about the deep injustices of the caste system, his ideological rift with Mahatma Gandhi, and his critical view of the Indian independence movement, which, in his opinion, did not represent the interests of the oppressed classes.

On the Caste System

Ambedkar's critique of the caste system was uncompromising. “Caste is not just a division of labour, it is a division of labourers,” he asserted in various writings, a sentiment echoed in his interview. He denounced caste as a system rooted in graded inequality and hereditary status, which denied basic human rights and dignity to vast sections of Indian society.

He rejected the notion that caste could be reformed from within the Hindu social order. According to him, caste was a rigid, inhuman hierarchy sustained by religious and cultural norms that needed complete dismantling, not just cosmetic reform.



On Mahatma Gandhi

The interview also touched upon his complex and often adversarial relationship with Mahatma Gandhi. While both leaders sought upliftment for the oppressed, their methods and ideologies starkly diverged. Gandhi advocated for the abolition of untouchability but maintained support for the broader varna system, which Ambedkar believed perpetuated inequality.

Gandhi was never against caste. In fact, he believed in varna, and his idea was that each person should do the job they are born into,” Ambedkar said. This fundamental disagreement came to a head during the Poona Pact of 1932, when Ambedkar was forced to give up his demand for a separate electorate for Dalits under immense pressure, including a hunger strike by Gandhi.

Ambedkar later wrote that

the Pact was a compromise made under duress, and that Gandhi's actions, while politically effective, ultimately delayed the full political empowerment of Dalits.

On the Freedom Struggle

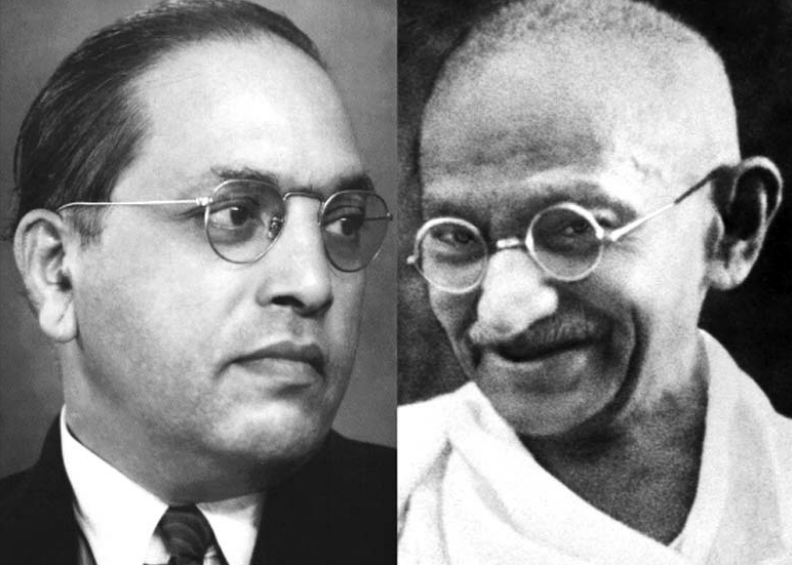
While Ambedkar welcomed the end of British colonial rule, he did not romanticize the nationalist movement. He believed that the struggle for freedom had largely been led by upper-caste elites who failed to include Dalit voices or address their suffering. “What use is political freedom if the social structure remains oppressive?” he questioned in various speeches.

This point is clearly echoed in the BBC interview, where he stresses that independence did not automatically translate into social justice. The challenges of caste, landlessness, and poverty persisted, especially for India's most vulnerable communities.

Legacy and Relevance Today

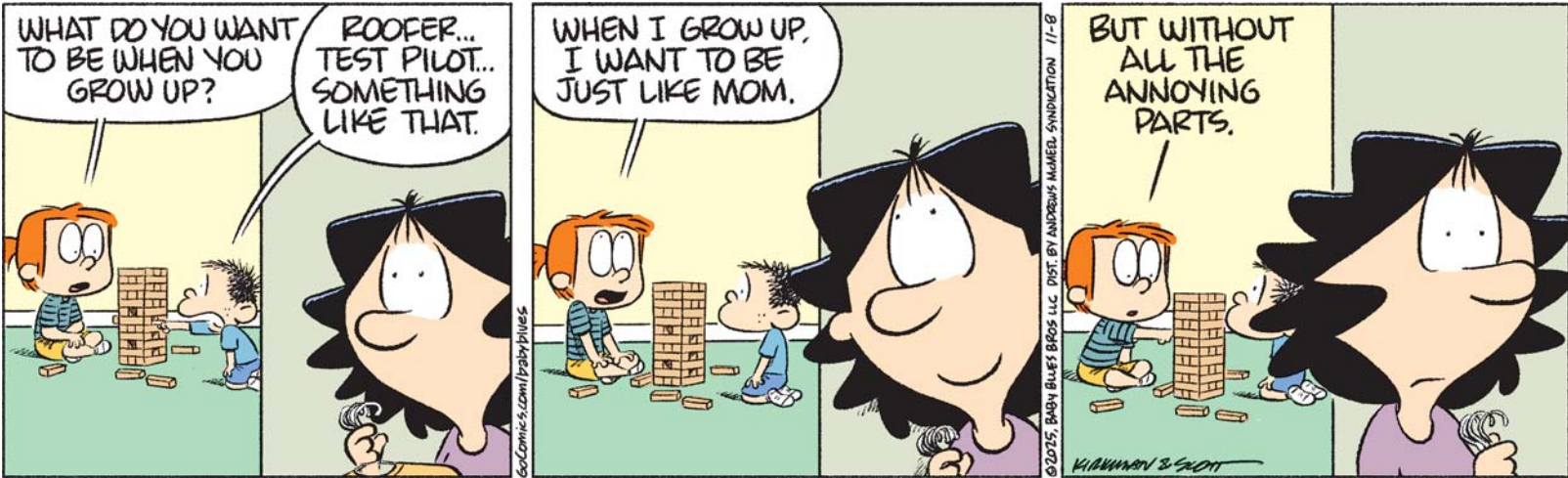
Dr. Ambedkar's 1955 interview remains deeply relevant in today's India. In an age where caste discrimination still surfaces in both overt and subtle forms, from manual scavenging and honour killings to unequal access to education and employment, his words continue to serve as a call to action.

His legacy extends beyond his role in framing the Constitution. By choosing to convert to Buddhism in 1956 along with hundreds of thousands of followers, he sent a powerful message of spiritual and social emancipation. His vision of an India built on liberty, equality, and fraternity still defines the aspirations of a democratic nation.



By Rick Kirkman & Jerry Scott

BABY BLUES



ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

संक्षिप्त

20 लाख रुपए की स्वीकृति जारी

मनोहरपुर, (निसं)। ग्राम लोचुकाबास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को जिला खनिज निधि ट्रस्ट योजना के तहत कक्षा कक्ष मय बरामदा व फर्श निर्माण के लिए ईजीनियरों की टीम भौतिक निरीक्षण के लिए विद्यालय पहुंची। भाजपा नेता गणपत वर्मा ने बताया कि विद्यालय के कुछ कक्षा कक्ष क्षतिग्रस्त होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिस पर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने जिला खनिज निधि ट्रस्ट योजना के तहत 20 लाख रुपए के राशि स्वीकृत की है। इस निर्माण कार्य को मूर्त रूप देने के लिए जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता विजय जलोबा, सहायक अभियंता शंकरलाल, कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र यादव, संजय वर्मा सहित अन्य सदस्य पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य रूपरेखा को अंतिम रूप देते हुए विद्यालय के कमरा नं0 6 व 7के उपर कक्षा कक्ष का निर्माण तथा कमरा नंबर 15 एवं 16 की छत की पटिटया हटाकर आरसीसी का निर्माण कार्य करवाने की बात कही।इस दौरान प्रधानाचार्य उमेश चंद्र शर्मा, उप प्रधानाचार्य मनोज शर्मा, बंशीधर पटवारी, सहित मौजूद थे।

संविधान दिवस

मनाया

शाहपुरा, (निसं)। अजित कुमार हींगर एवं सचिव पवन कुमार जीनवाल के निदेशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा अध्यक्ष ललित शर्मा अग्र जिला एवं सत्र सेशन न्यायाधीश प्रथम की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एडीजे ललित शर्मा ने संविधान की प्रस्तावना का सघी उपस्थित कर्मचारी गणों एवं एडवोकेट्स को वाचन करवाकर उनकी शपथ दिलाई गई। भारत के संविधान के बारे जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम में शाहपुरा सहायक नाजिर मुकेश कुमार शर्मा, विधिक सेवा प्रभारी अमय मीणा, अधिकार मित्र दिनेश कुमार शर्मा, लीगल कमी मत्ता परसानिया एवं समस्त शाहपुरा न्यायालय के कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, वरिष्ठ प्रो.बोनी, अधिवक्ता सीताराम सोलादार, शिवकुमार शर्मा, गिरधारी नारायण, रवि शंकर अग्रवाल, नरेश कुमार शर्मा, मुकेश कुमार व्यास एवं अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित थे।

गौवंश से भरी पिकअप जब्त

टोंक, (निसं)। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वृताधिकारी उनीयारा अनुज डाल के सुपरविजन में एवं निवाई सदर थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बुधवार को गौ गश्त के दौरान निवाई क्षेत्र के भर्जियां की ढाणी प्रतापपुरा रोड से ग्राम सुरया की तरफ जा रही एक पिकअप को चैकिंग के दौरान वाहन में गोशरा भर मिलने पर मौके पर ही अवैध रूप से गोवंश परिवहन करते हुये पाये जाने पर पिकअप को जप्त किया गया। कार्रवाही के दौरान चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।

1 रुपया लेकर दहेज का किया त्याग

टोंक, (निसं)। वर्तमान में जहां दहेज एक दानव की तरफ फैलता जा रहा है, वही मुख्यालय के खोजा बावडी में हुए एक शादी के दौरान दुल्हे ने दहेज के नाम पर केवल लगन, टीका और शादी में एक रुपया, पौधा व कलश लेकर के समाज का नाम रोशन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खोजा बावडी निवासी प्रताप मल बैरवा की लडकी पूजा सिसोदिया का विवाी रामप्रसाद बैरवा निवासी वीरपुर तहसील खंडार जिला सर्वाईमाधोपुर हुआ है, जिसमें दुल्हे ने दहेज को समाज में एक कुरीति बताते हुए बहिष्कार कर दिया। वहीं दुल्हे ने इस अवसर पर केवल लगन, टीका और शादी में एक रुपया लेकर रिश्ता निभाया तथा समाज में ऐसे रीति को हटाने तथा हर घर व अपने आस पास पौधा लगाने का संदेश दिया।

वन्दे मातरम् का सामूहिक गान

टोंक, (निसं)। राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रमुख कक्ष मे जिला प्रमुख सरोज बंसल ने गीत का शारुष्टिक गान किया। इस दौरान वन्दे मातरम् की ऐतिहासिक यात्रा, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम में इसके अमूल्य योगदान पर चर्चा की गई। जिला प्रमुख ने बताया कि वंदे मातरम् स्वदेशी आंदोलन से आत्मनिर्भर भारत तक 1905 में वंदे मातरम् बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बना देशवासियों ने लगाकर स्वदेशी सामान को अपनाया।

विराटनगर के सूरजपुरा को ग्राम पंचायत नहीं बनाने पर विरोध प्रदर्शन किया

पावटा, (निसं)। विराटनगर क्षेत्र के ग्राम सूरजपुरा को ग्राम पंचायत का दर्जा न दिए जाने पर ग्रामीणों द्वारा चौथे दिन भी धरना व विरोध प्रदर्शन एवं आमरण अनशन कर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सूरजपुरा आबादी और अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है, फिर भी इसे ग्राम पंचायत नहीं बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि कुछ अन्य ग्राम पंचायतों को, जो मापदंड पूरे नहीं करतीं, उन्हें भी यह दर्जा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे ग्राम सूरजपुरा को स्वतंत्र ठाम पंचायत घोषित किया जाए, पंचायत पुनर्गठन प्रस्ताव की निष्पक्ष समीक्षा की जाए, नियमों के हिसाब से ग्राम सूरजपुरा ग्राम पंचायत के लिए संपूर्ण मापदंड पूरे करता है, ग्राम सूरजपुरा में पंचायत भवन हेतु पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। पूरा नहीं किया जाता है तब तक पंचायत गठन सूरजपुरा के अन्याय व न्याय तक संघर्ष जारी रखते हुए धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन जारी रहेगा।

कांग्रेस पावटा ब्लॉक अध्यक्ष महादेव प्रसाद ने कहा कि वास्तव में यह अत्यंत दुःखद एवं चिंताजनक है कि आम जनता अपनी न्यायोचित मांगों को



विधायक कुलदीप धनकड ने आमरण अनशन पर बैठे चार लोगों को जूस पिलाकर आमरण अनशन व लोगों को आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया।

मनवाने के लिए इस स्तर तक मजबूर हो रही है, फिर भी उनकी आवाज सत्ता के कानों तक नहीं पहुँच रही। भाजपा के पदाधिकारियों एवं प्रशासन से मजबूत आग्रह नहीं, बल्कि आग्रह के साथ आह्वान करता हूँ कि मानव जीवन की गंभीरता को समझें, जनता की भावनाओं का सम्मान करें, संवाद

स्थापित कर तुरंत समाधान निकालें, इस भूख हड़ताल एवं धरने को शीघ्र समाप्त करवाएँ। सबकी यही अपेक्षा है कि जनता हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाए, समस्याओं का त्वरित समाधान हो जिससे क्षेत्र की शांति एवं स्वास्थ्य की रक्षा हो। दोनों गाँवों को अलग-अलग पंचायत का दर्जा दिया जाए क्योंकि ऐसा

होने से दोनों क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा, प्रशासनिक सुविधाएँ लोगों तक सीधी पहुँचेंगी, किसी भी गाँव को उपेक्षित महसूस नहीं होगा, जनता को बेहतर योजनाएँ और संसाधन मिल सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण दोनों गाँवों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, वह शांत होगा। अलग-अलग पंचायत बनने से दोनों गाँवों का

- ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सूरजपुरा आबादी और अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है, फिर भी ग्राम पंचायत नहीं बनाया जा रहा**

- चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन रहा जारी**

विकास होगा, भाईचारा बढ़ेगा और क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा। वहीं गुरुवार को विधायक कुलदीप धनकड ने धरने पर पहुँचकर ग्रामीणों सेसमझाइश कर जन भावनाओं को देखते हुए पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए ग्राम सूरजपुरा को ग्राम पंचायत बनाए जाने या कोई अन्य तरीके से समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक कुलदीप धनकड ने आमरण अनशन पर बैठे चार लोगों हितेंद्र सिंह, नवदीप सिंह, हितेंद्र, सुभाष को जूस पिलाकर आमरण अनशन व आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। इस मौके पर बडी संख्या में ग्रामीण व महिलाएं मौजूद रही।

दूषित पानी की सप्लाई से वार्डवासी परेशान

पावटा। कस्बे के वार्ड नंबर 11 के लोग कई दिनों से काले रंग व झाग वाले दूषित पानी की सप्लाई से परेशान हैं। जलदाय विभाग की ओर से सप्लाई होने वाला पानी इतना गंदा है कि इससे बंदबू आती है। पानी का रंग काला है व पानी में झाग भी बन रहे हैं।

राधेश्याम सोनी, हिमांशु गोयल, डॉ ओमप्रकाश गौड, संतोष सोनी, योगेश गोयल, नीरज सैन, वीरेंद्र बंसल, रामेश्वर यादव, मुकेश जिंदल, श्रवण बंसल सहित वार्डवासियों ने बताया कि इसके चलते पानी की टंकियां भी गंदी हो गई हैं। लोगों को टंकियों की सफाई करानी पड़ रही है। वैसे भी पानी की सप्लाई बहुत कम होती है। घंटों तक लोगों को पानी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब जो पानी की सप्लाई हो रही है, वह किसी काम की नहीं है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के द्वारा लोगों की सेहत से पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है।



वार्ड नंबर 11 के लोग दूषित पानी की सप्लाई से परेशान।

मजबूरी में लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि उस पानी का इस्तेमान घर की साफ-सफाई में भी नहीं किया जाता। जहां एक ओर घर के नलों में काले रंग का दूषित पानी आ रहा है, वहीं दूसरी ओर पानी में झाग भी बन रहे हैं। वार्ड में बंदबूदार पानी

की सप्लाई होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुकेश सोनी ने बताया कि कॉलोनी के सकानों में बंदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। पानी काला, दूषित व झागदार होने से इतनी ज्यादा बंदबू आती है कि उसे बयां करना मुश्किल है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज का प्रथम बैच प्रारम्भ

टोंक, (निसं)। राजकीय मेडिकल कॉलेज टोंक ने अपने पहले एमबीबीएस बैच के आगमन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थियों व परिजनों ने व्हाइट कोट सेरेमनी हर्षोल्लास से आयोजित की गई, यह समारोह चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जिले के लिए नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।

इस कार्यक्रम में आई.एम.ए. सचिव डॉ. राजीव बंसल, डॉ. शानू बंसल, शशि चौधरी, दिलीप चौधरी तथा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. लोकेन्द्र शर्मा उपस्थिति रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों ने नव-प्रवेशित विद्यार्थियों को

चिकित्सकीय दायित्वों एवं आचार-संहिता से परिचित कराया। इस मौके पर डॉ. राजीव बंसल ने विद्यार्थियों को एम.एस.एन. (मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क) की कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा बताया कि एम.एस.एन. चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए एक सशक्त मंच है, जो उन्हें अकादमिक, अनुसंधान, नेतृत्व तथा सामाजिक चिकित्सकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। वहीं डॉ. शानू बंसल ने विद्यार्थियों को चिकित्सकीय नैतिकता, मानवता तथा रोगी-सेवा के मूल्यों पर आधारित सफेद कोट की परंपरा का महत्व समझाया।

परमात्मा पूजा से नहीं पुरुषार्थ से मिलेंगे : प्रबुद्ध सागर

निवाई। सन्त निवास नसियां जैन मंदिर में सकल दिग्गम्बर जैन समाज के तत्वावधान में आचार्य वर्धमान सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रही। सर्व प्रथम प्रातःकाल में जिनोदय युवा संघ एवं श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव के साथ संघ को श्रीफल भेंट किया।

जैन समाज के प्रवक्ता सुनील भाणजा एवं हितेश छाबडा ने बताया कि भगवान शांतिनाथ, आदिनाथ व

धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

पाश्र्वनाथ का अभिषेक एवं शान्तिधारा की गई। इसके पश्चात आचार्य शांतिसागर महाराज व वीर सागर महाराज के चित्र समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किया गया। कार्यक्रम का मंगलाचरण णमोकार महिला मण्डल द्वारा किया गया। मुनि प्रबुद्ध सागर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन की मूल समस्याओं का समाधान अध्यात्म

द्वारा ही संभव है। अध्यात्म मानव चेतना को उसे अनंत ऊंचाई तक ले जाता है। जहां से पुनः लौटना नहीं होता, आगम शब्दों में जिसे निर्वाण और मोक्ष कहा जाता है। उन्होंने निर्वाण और मोक्ष की परिभाषा बताते हुए कहा कि मन से वासना का बाण निकल जाना ही निर्वाण है और मोह का अभाव ही मोक्ष है। मोक्ष विरासत में अथवा उत्तराधिकारी के रूप में मिलने वाली संपत्ति नहीं है। उसे अपने ही श्रम से अर्जित करना पड़ता है। भगवान महावीर की संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा गया है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर महिलाओं को शपथ दिलाई

राजगढ़, (निसं)। कस्बे के पुलिस थाना परिसर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर महिलाओं को शपथ दिलाई। महिला अधिकारिता विभाग अलवर की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर पर्यवेक्षक अभिलाषा शर्मा ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अनुदानित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र व गणनायक विकास संस्था जयपुर की

महिलाओं से ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह नहीं करने के बारे में जन चेतना जागृत करने की अपील की

ओर से आयोजित किस कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर इस अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जनसंपर्क का आ्ग किया गया। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की विधि सलाहकार उषा जाजू में बाल विवाह की गंभीर अपराध बताते हुए इसके कानूनी



पुलिस थाना परिसर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर महिलाओं को शपथ दिलाई।

प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह करने वाले एवं सहयोग करने वालों पर दंड का प्रावधान है।

इस दौरान महिला सलाहकार ज्योति शर्मा ने बाल विवाह को लडके एवं लडकी के विकास में बाधक बताया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह नहीं करने के बारे में

जन चेतना जागृत करने की अपील की। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाएं एवं अन्य मौजूद रहे। संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह बबेली ने बताया कि पंचायती राज के संयुक्त विधि परामर्शी गिरवर सिंह शेखावत से सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास

अधिकारी से विकास अधिकारी पद पर पदोन्नित बाबत स्थाई वरीयता सूची जारी करने की मांग की। इस पर उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संगठन के महामंत्री रामचंद्र मीणा, सोहनलाल, हरफूल मीणा, जयपुर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादीन, सुबे सिंह शर्मा, एवं अन्य मौजूद रहे।

सार-समाचार

भूमाफियाओं से मिलीभगत का आरोप

अलवर, (निसं)। देसुला गांव के पटवारी दिनेश कुमार ने दावा किया था वे अपने क्षेत्र की गोचर भूमि पर अवैध प्लांटिंग नहीं होने देंगे, लेकिन उनके दावों की आज भूमाफियाओं ने हवा निकालते हुए आज फिर प्लांटिंग शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी के सारे दावे झूठे हैं। पटवारी और तहसीलदार की मदद से ही यहां प्लांटिंग की जा रही है। वहीं जब तहसीलदार से फोन पर बात की तो उन्होंने फोन नही उठा कर यह दर्शा दिया वे इस बारे में कोई सफाई नहीं देना चाहती है। यहां पर उल्लेखनीय है कि शहर के नजदीक गांव देसुला में गोचर भूमि पर लगातार प्लांटिंग जारी है और यहां एक तो भवन भी पूरी तरह बन चुका है। इसकी सूचना जब ग्रामीणों ने मीडिया को दी तो मीडिया ने मौके पर जाकर जानकारी जुटाई तो पाया कि खसरा नं 534 पर अवैध प्लांटिंग की जा रही है। जिस पर मीडिया ने पटवारी दिनेश कुमार को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने शाम को फोन पर बताया और दावा किया कि उन्होंने जाकर काम रूकवा दिया है। अधिकारियों को सूचित कर दिया है। आगे से उनके क्षेत्र में कोई भी भूमि पर प्लांटिंग नहीं की जा सकती। उनके बयान को आधार बना कर मीडिया में खबर चलाई गई। लेकिन पटवारी के दावे की दूसरे दिन ही भूमाफियाओं ने हवा निकाल दी। यहां बुधवार को भी काम ज़ोरों से चलता दिखाई दिया। जब सुबह करीब बस बजे पटवारी को इस निर्माण कार्य की सूचना दी तो पटवारी दिनेश कुमार ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सूचित कर दिया है। कार्रवाई और एफआरआर का काम तो उच्च अधिकारी ही करेंगे। पटवारी की बात को आधार मानते हुए जब अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा से फोन पर बात करने के कई बार प्रयास किए गए लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। ग्रामीणों ने पटवारी और तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना अधिकारियों की शह से कोई भी भूमाफिया प्लांटिंग नहीं कर सकता है। यह सारी प्लांटिंग का खेल पटवारी तहसीलदार सहित उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है।

एनसीसी दिवस मनाया

टोंक, (निसं)। मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य लोकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एनसीसी दिवस मनाया गया, जिसमें कैडेट्स ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान प्राचार्य शर्मा ने कहा कि एनसीसी युवाओं में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और संवेदनशील नागरिकता का भाव जगाने वाला एक सशक्त मंच है। यह एक ऐसा प्रशिक्षण है जो शिक्षा, फिटनेस और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने विभिन्न युद्धों एवं आपदाओं के समय एनसीसी की भूमिका को रेखांकित करते हुए कैडेट्स में देशभक्ति, राष्ट्रनिर्माण व सेवा भावना का संदेश दिया।

एम-सैंड फैक्ट्री का शुभारम्भ

निवाई। राज्य सरकार की एम-सैंड पॉलिसी एवं आरआईपीएस पॉलिसी के अंतर्गत गांव गुसी में एम-सैंड निर्माण इकाई सारथी जियोटेक प्राइवेट लिमिटेड का विधिवत शुभारम्भ किया गया। एम-सैंड का शुभारम्भ प्रमुख उद्योगपति ओ.पी. गुप्ता, फैक्ट्री निदेशक कुशाठा गुप्ता व जीएम संजय जैन ने विधिवत पूजा-अर्चना करके फीता काटकर किया। डायरेक्टर कुशाठा गुप्ता ने बताया कि बजरी की लगातार कमी और एक सार क्वालिटी उपलब्ध नहीं होने की समस्या का समाधान एम-सैंड होगा। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक बजरी में क्वालिटी की समानता संभव नहीं हो पाती, जबकि एम-सैंड एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनकर अधिक टिकाऊ और बेहतर गुणवत्ता प्रदान करती है। इससे नदी संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। डीआईसी के जीएम संजय जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यों में 25 प्रतिशत एम-सैंड का उपयोग अनिवार्य कर दिया है तथा इसे भविष्य में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

ड्राइवर से मारपीट, बस के शीशे तोड़े

अलवर, (निसं)। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात रोडवेज बस ड्राइवर से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। कुछ युवकों ने रोडवेज ड्राइवर प्रीतम के साथ जमकर मारपीट की। कुछ युवकों ने रोडवेज ड्राइवर प्रीतम के साथ जमकर मारपीट की और बस के शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ड्राइवर प्रीतम ने शिकायत में बताया कि वह दिल्ली से अलवर बस लेकर लौट रहा था। जब बस बिजली घर चौराहे के पास पहुंची तो एक स्कूटी सवार युवक लगातार बस के आगे स्टंट कर रहा था। स्कूटी पर युवक के साथ दो लड़कियां भी सवार थीं। लापरवाही इतनी थी कि स्कूटी बस से टकराने से बाल-बाल बची। ड्राइवर ने जब उन्हें रोका-टोका तो बहस हो गई। उसी दौरान करीब आठ युवक वहां आ गए और उसके साथ लात-थुंसे और डंडों से हमला कर दिया। आरोपी युवकों ने बस के शीशे भी चकनाचूर कर दिए। मारपीट के बाद सभी युवक मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और ड्राइवर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

पेयजल संकट, ग्रामीण परेशान

निवाई। गांव चनानी में बीसलपुर पेयजल योजनांतर्गत एक महीने से पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है जिससे ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीण मनभर यादव, गीता प्रजापत, काली मीणा, बादाम प्रजापत, सीता यादव, शायर मीणा, गोरा बैरवा व सुरज्ञान गुर्जर ने बताया कि गांव में बीसलपुर परियोजना के तहत लगाए गए पॉइंट में करीब एक सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है। जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। जिसको लेकर महिलाओं को करीब एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने लगातार पेयजल सप्लाई करने की अधिकारियों से मांग की है।

लवणीय झील में झपोक डेम के नजदीक बनेगी “टेंट सिटी”

सांभरझील, (निसं)। सांभर लवणीय में आने वाले कुछ समय में झपोक बांध के नजदीक टेंट सिटी बनने जा रही है। जानकारी में आया है कि योजना के तहत टूरिज्म विभाग (या राज्य पर्यटन निगम) इसे पीपीपी मॉडल पर करना चाहता है। लगभग 1०0 बीघा जमीन (करीब हेक्टेयर) पर एक टेंट सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव है जिस पर करीब चार करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। यह टेंट सिटी, गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर यानी पर्यटन माहौल विकसित करने का विचार है। जानकारी में आया है कि अभी कुछ तकनीकी व अन्य कारणों से टेंट सिटी का चल रहा काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है लेकिन शीघ्र ही इसको गति मिलने लग जाएगा। झील और उसके आसपास इलाकों में सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इस तरह, लेक-टूरिज्म पक्षी-प्रेक्षण, प्राकृतिक सौंदर्य झील-वैकल्पिक अनुभव टेंट सिटी बनने के बाद आने वाले पर्यटकों को होंगे। पर्यटक अनुभव विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

भूमिका सैनी ने 1250 फीट की ऊंचाई से पैराशूट जम्प किया

सांभरझील, (निसं)। भाजपा के पूर्व पार्षद दंपति शंभू दयाल-पुष्पा देवी सैनी व माली समाज के अध्यक्ष रहे भगवान सहाय माली की दोहरी भूमिका सैनी ने 1250 फीट ऊंचाई से पैराशूट जंप कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इनकी माता माला सैनी साधारण गृहणी है जबकि पिता गुडा साल्ट में फोटो व वीडियोठापी के व्यवसाय से जुड़े हैं। बता दें कि राजकीय शाकम्बर पीजी कॉलेज सांभर की छात्रा भूमिका सैनी फर्स्ट र‍ैंज बटालियन एनसीसी, जयपुर की एकमात्र ऐसी कैडेट है जिनका चयन देश के प्रतिष्ठित नेशनल पैरा बेसिक कैप के लिए हुआ है सम्पूर्ण देश से कुल 60 कैडेट्स जिनमें राजस्थान से केवल तीन सर्वश्रेष्ठ छात्राओं और एक छात्र का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था। यह बताना भी जरूरी है कि नेशनल पैरा बेसिक कैप एनसीसी का सबसे कठिन और गौरवशाली प्रशिक्षण कार्यक्रम माना जाता है जिसका आयोजन एयरफोर्स की पैराट्रूप स्कूल, आगरा द्वारा किया जाता है। इसमें कैडेट्स को एयरबोर्न ट्रेनिंग, टाउंडंड ट्रेनिंग तथा वास्तविक पैराशूट जंप की तैयारी करवाई जाती है। भूमिका सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव बहुत अद्भुत रहा।

बीएल सैनी को दी श्रद्धांजलि

शाहपुरा, (निसं)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सड़क मार्ग से पटेल नगर अमरसर शाहपुरा में पहुंचे जहां पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पूर्व सदस्य बीएल सैनी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित उनको श्रद्धांजलि दी। राजकीय शिक्षक बीएल सैनी का किम्वदंत आकस्मिक निधन हो गया था। गहलोत के साथ शाहपुरा विधायक मनीष यादव, कांग्रेस के नेता प्रवीण व्यास, संदीप चौधरी आदि मौजूद रहे।

